MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) No Sir.

(b) Postings of officers on diplomatic assignments are based on functional requirements and there is no restriction on officers being posted to the same country more than once if it is functionally desirable to do so.

(c) and (d) Question does not arise.

3906. *[Transferred to 26th August, 1993]*

देश में दुग्ध-उत्पादन

3907. **डा० जितेन्द्र कुमार** जैन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गत वर्षों के दौरान दूध के उत्पादन में भारी वृध्दि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में दूध पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता में भी अब वृध्दि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के रूप में दूध पर आधारित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो उस लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा ऐसे एकक स्थापित करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का निर्णय किया गया है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण करके विभिन्न दुग्ध-उत्पाद तैयार करने वाले कुल कितने औद्योगिक एकक कार्यरत थे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) जी, हां। दुग्ध उत्पादन 1987-88 में 46.7 मिलियन टन था जो 1992-93 में बढ़कर 58.6 मिलियन टन हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दुग्ध उत्पाद तैयार करने को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कुटीर स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध एवं आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त में संगठित सेक्टर में 74 यूनिट थे जो विभिन्न दुग्ध-उत्पाद तैयार करने के लिए दुग्ध प्रसंस्करण में लगे हुए थे।

Italian company setting up Candies and Chewing-gum Units

*3908. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Italian Company is setting up Candies and Chewing-gum Units in the country and expected to go in production by January, 1994;

(b) if so, whether the Company is entering into the Indian market in a joint venture, if so, the details thereof; and

(c) if not, what are its likely implications/impacts on the indigenous industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) M/s. Perfetti SPA, Italy have been granted approval to set up a plant for manufacturing chewing-gum and toffees with 51% foreign equity, amounting to Rs. 9.69 crores in the paid-up capital of Rs. 19 crores. The company has reported that this plant is expected to go into production in the first quarter of 1994. The company has an obligation to export products of the value of at least Rs. 42 crores over a period of seven years.

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन

3909. **श्री हरि वल्लभ यादव**: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निवेश द्वारा किन-किन उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (ग) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में कुछ सेक्टरों से संबंधित अध्ययन उपलब्ध है परन्तु इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में पूंजीनिवेश की गुंजाइश का आकलन करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। फिर भी खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में ऐसे अध्ययन करने के लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों, दूसरे संस्थानों एवं संगठनों को सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार

* Previously Unstarred Question 3224, transferred from 19th August, 1993.

की हैं । जिनका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना या उनके विस्तार, किसानों के साथ पिछड़े संपर्कों को विकसित करने, विपणन सहायता आदि के लिए राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, संयुक्त सेक्टर यूनिटों, सहायित सेक्टर यूनिटों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को सहायता प्रदान करना है । मंत्रालय का इरादा उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना है जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, डेरी, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण, खाद्यान्न प्रसंस्करण और पुष्प प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं ।

वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों पर मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गयी सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	सेक्टर	दी गयी सहायता (रुपये लाखों में)	उद्देश्य
1992-93	मांस और उत्पाद	1.26 लाख	कारीगरों का प्रशिक्षण ।
—	— तदैव —	2.10 लाख	मांस के भंडारण के लिए विपणन सहायता ।
—	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	54 लाख	खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।
—	— तदैव —	5 लाख	विपणन सहायता ।
—	— तदैव —	3.50	नोडल एजेंसियों को सुदृढ़ करना ।

Clearance of Coca Cola Projects

3910. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government have cleared Coca Cola project for setting up a 100 per cent owned venture in India, to manufacture beverages;

(b) if so, what are the details of the project; and

(c) what is Government's policy in respect of such food processing industries for inviting foreign investments ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) Details are given in the statement (*see* below).

(c) Automatic approval for foreign technology agreement and for 51% foreign equity participation are granted for high priority industries listed in Annexure-III to the new Industrial Policy announced in 1991. All other proposals which do not qualify for automatic approval are considered on merits by the Government. Approval for Non-Resident Indians and Overseas Corporate Bodies predominantly owned by them, for investment up to 100% equity in high priority industries, are also permitted.

Statement

Government have approved the proposal from M/s. Coca Cola South Asia Holdings Inc. USA for the manufacture of beverage bases and essences. The Company will have 100% foreign equity amounting to Rs. 60 crores by itself or through its subsidiaries/associate companies. The company will maintain an export-import ratio of 3 : 1. There will be dividend balancing for seven years from the date of commencement of production and this will be over and above the 3 : 1 export-import ratio separately stipulated. The company offered to make the following commitments, which have been noted :—

(i) Company does not envisage any payment of technical/license fees, payment for the use of patents, royalties, training fees or any other consultancy lump sum payment.

(ii) The projected imports of essential flavouring essences is Rs. 78 crores in the first seven years.

(iii) The estimated inflow of foreign exchange by exports is Rs. 234 crores over the first seven years.

(iv) There will be no remittance of dividents for the first seven years

Production of Beer in the Country

3911. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :

DR. NAUNIHAL SINGH :